(ग) क्या इसमें अगस्त्य मुनि जलागम विकास परियोजना, जिला चमोली की 7.95 करोड़ रुपए की योजना भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशी सहायता हेतु चार प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं यथा (1) कुचगाड तथा उत्तरी कोशी एकीकृत पनधारा प्रबंध परियोजना; (2) बेनलगाड एकीकृत पनधारा प्रबंध परियोजना; (3) पनधारा प्रबंध के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की पारिस्थितिकी का पुनः स्थापन और विकास; तथा (4) अगस्त्य मुनि एकीकृत पनधारा प्रबंध परियोजना।

उपर्युक्त चार परियोजना प्रस्तावों में से, क्रम संख्या (1), (2) और (3) पर उल्लिखित प्रस्ताव विदेशी सहायता हेतु क्रमशः यूरोपीय कमीशन के प्रतिनिधि मंडल, रायल नीदरलैंड दूतावास तथा विश्व बैंक के समक्ष रखे गए हैं; और क्रम संख्या (4) पर दिए गए प्रस्ताव में राज्य द्वारा सुधार किया जा रहा है।

दक्षिण भागीरथी चरण-3 पनधारा विकास परियोजना प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र का विकास कार्य यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता प्राप्त चल रही टून घाटी पनधारा विकास परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है।

State Farms Corporation of India

3222. SHRI AMAR SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the chairman, State Farms Corporation of India is still continuing despite the fact that he was superannuated on February 28, 1998 and if so, under whose orders he has been continuing; and

(b) whether it is a fact that his services were also terminated by Government and if so, on what grounds?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

Threat by Genetically Engineered Seeds

3223. SHRI K.R. MALKANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of genetically engineered seeds containing the newly Patented Terminator gene-jointly developed by U.S. Agriculture Department and Delta and Pineland, and MNC, that switches off the reproductive cycle of a plant after a generation, as reported in the Observer dated the 17th June, 1998.

(b) whether this suicidal gene would necessitate purchase of new Patented Seeds every season by the poor farmers;

(c) whether this gene could spread to other crops also and play havoc with our food self-sufficiency and food security; and

(d) what measures Government are taking to stop this killer gene from ever invading India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir.

(b) The technology would necessitate purchase of new seeds every year in crops/varieties where it is introduced.

(c) It has been concluded by a number of crop geneticists that there is a likelihood of the pollen carying Terminator trait pollinating the crops in adjoining farmer's fileds. The seeds from such affected plants would again be sterile, thus resulting in poor crop stands, and far more importantly, gradual extinction of traditional varieties.

Furthermore, crop related weeds, important for natural evolution of crop species, may be affected. This concern is of special relevance to India since the country is rich in land races and wild relatives of crop plants.

There also has been an opinion that since the seed carries the sterility trait, it is less likely that transgenic material will

escape from one crop into related species and wild crop relatives. Even if the effect is there, further escape is checked due to mortality of varieties/hybrids. Nevertheless. biosafety at the expense of food security is no solution.

(d) Indian Council of Agricultural Research has seriously taken note of this issue as early as March, 1998. In May, 1998 a meeting on the issue was held and the Directorate of Plant Protection for Quarantine and Storage (Department of Agriculture and Cooperation, Government of India) has issued the office memorandum no. 82-1/98-PPD dated 25.5.98 whereby the following steps were taken to stop the killer gene from invading India:—

(i) In no case any seed material having Terminator Gene should be imported.

(ii) Before issuing Import Permits for Seeds, Import Permit Issuing Authorities should satisfy themselves that such seeds are not having Terminator Gene.

(iii) Import Permit Issuing Authorities should request the Importers to help in getting an additional declaration on the official Phyto Sanitary Certificate that the imported seeds (By Name) are free from Terminator Gene.

(iv) Before release of imported seeds, Import Permit Issuing Authorities should satisfy themselves that such seeds do not contain Terminator Gene.

(v) Import Permit for any kind of Seed falling under the Category of "Trans-genic Material" must not be issued without the approval of PPA (Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India).

किसानों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने के मानदण्ड

3224. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री रामगोपाल यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाली क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का मानदण्ड एवं प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित कृषक परिवारों को पचास प्रतिशत फसल की क्षति पर सरकार द्वारा कोई सहायता राशि नहीं दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं तो अग्नि कांड, ओला-वृष्टि, अतिवृष्टि, तूफान आदि से होने वाली जन-धन एवं फसलों की क्षति पर सरकार किस प्रकार से व किस सीमा तक सहायता प्रदान करती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) से (ग) दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में गठित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर, कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से स्वीकार्य सहायता की मदों और मानकों की सूची भेज दी है ताकि वे आपदा राहत निधि से सहायता के अपने मानकों को अंतिम रूप दे सकें। इन मानकों में अन्य बातों के साथ-साथ मृत व्यक्ति के परिवार को 20,000/-रु० की अनुग्रह राशि का भुगतान, छोटे और सीमान्त किसानों को, जिनके फसल क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 500 रु० प्रति हैक्टेयर की दर पर आदान सब्सिडी के रूप में सहायता और पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त मकान को पुनः स्थापित और निर्मित करने के लिए, 4000/-रुपए की सहायता, पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण के लिए 2000/- रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के लिए 800 रु० की सहायता शामिल है। स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्यों को अनेक मदों में इन मानकों से 50 प्रतिशत तक विमुक्त रखने की अनुमति दी गई है।